

इंडिगो की उड़ानों पर बढ़ा ईंधन शुल्क, घरेलू यात्रा में 1,300 रुपये तक अतिरिक्त खर्च

इंडिगो ने बढ़ाया फ्यूल चार्ज आज से हवाई सफर होगा महंगा



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हवाई यात्रियों को झटका देते हुए उड़ानों पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरें 6 अक्टूबर की रात 12:01 बजे से लागू होंगी। इसके बाद घरेलू उड़ानों में यात्रियों को 1,300 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 10,000 रुपये तक अतिरिक्त

फ्यूल चार्ज देना होगा। एयरलाइन ने छह महीने के भीतर तीसरी बार यह शुल्क बढ़ाया है।

इंडिगो के अनुसार, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण फ्यूल चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले एयरलाइन ने इस साल 14 मार्च और फिर 1 अप्रैल को

भी किएए में बढ़ोतरी की थी।

जेट फ्यूल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी

हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में अक्टूबर में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर से घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमत 121 रुपये से बढ़कर 137 रुपये प्रति लीटर हो गई। यानी एक लीटर जेट फ्यूल की कीमत में 16 रुपये या करीब 13.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले तीन महीनों में जेट फ्यूल की कीमत में कुल 27.28 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अगस्त 2026 में इसमें 5 रुपये, सितंबर में 6.28 रुपये और अक्टूबर में 16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इंडिगो के मुताबिक, पिछले एक महीने में

जेट फ्यूल की कीमत 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। इसके चलते विमान ईंधन की कीमत पिछले 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

एयरलाइंस के खर्च में ईंधन की बड़ी हिस्सेदारी

जेट फ्यूल एयरलाइंस के संचालन में होने वाले सबसे बड़े खर्चों में शामिल है। कुल परिचालन खर्च में इसकी हिस्सेदारी करीब 30 से 40 प्रतिशत तक होती है। ईंधन की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से एयरलाइंस के वित्तीय अनुमानों पर भी असर पड़ा है। दुनियाभर की कई एयरलाइंस बड़ी लागत का बोझ यात्रियों पर डाल रही हैं। एयर न्यूजीलैंड और क्वांटस जैसी कंपनियों ने भी बढ़े हुए खर्च की भरपाई यात्रियों से करने की बात कही है।

भारत में बनेगी कैमरा-केंद्रित एआई चिप, 130 करोड़ रुपये मंजूर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु स्थित बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स के साथ समझौता किया है। इसके तहत अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष से कंपनी को 130 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विजन सिस्टम-ऑन-चिप विकसित करना है। प्रोजेक्ट वीएएआई की कुल लागत 260 करोड़ रुपये है। परियोजना के माध्यम से तकनीक को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर यानी टीआरएल-5 से टीआरएल-9 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय सहायता वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से दी जाएगी। परियोजना के तहत कैमरा-केंद्रित एआई विजन सिस्टम-ऑन-चिप तैयार किया जाएगा, जो सुरक्षित, बुद्धिमान और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सेमीकंडक्टर समाधान उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। परियोजना का शुरुआती इस्तेमाल निगरानी व्यवस्था, विशेष रूप से सीसीटीवी प्रणालियों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशी स्तर पर विकसित सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करना है।

सीआईएल ने बढ़ाई बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आपूर्ति

पहले छह महीनों में बिजली क्षेत्र को 30.28 करोड़ टन कोयला भेजा



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की अहम भूमिका को देखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया है। कंपनी अपनी कुल कोयला आपूर्ति का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बिजली क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कोयले के उठाव और बिजली क्षेत्र को आपूर्ति में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई।

पहले छह महीनों में कोल इंडिया का कुल कोयला उठाव 38.42 करोड़ टन रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में यह 35.70 करोड़ टन था। इस तरह 2.72 करोड़ टन यानी 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही में उठाव 18.604 करोड़ टन रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 16.604 करोड़ टन से 12.05 प्रतिशत अधिक है। सितंबर में कंपनी की

कुल कोयला आपूर्ति 6.12 करोड़ टन रही, जबकि सितंबर 2025 में यह 5.44 करोड़ टन थी। इसमें 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली छमाही के दौरान कंपनी ने खदानों पर उपलब्ध करीब 6.3 करोड़ टन कोयला भंडार का भी उपयोग किया, जिससे आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिली। बिजली क्षेत्र को पहली छमाही में 30.28 करोड़ टन कोयला भेजा गया, जबकि पिछले वर्ष यह मात्रा 28.54 करोड़ टन थी। इसमें 1.74 करोड़ टन यानी 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के कुल कोयला उठाव में बिजली क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 79 प्रतिशत रही। दूसरी तिमाही में बिजली क्षेत्र को 14.82 करोड़ टन कोयला भेजा गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 13.35 करोड़ टन से 11 प्रतिशत अधिक है। पहली छमाही में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.89 करोड़ टन रही, जो सितंबर 2025 के 4.42 करोड़ टन से 10.63 प्रतिशत अधिक है। 28 से 30 सितंबर के दौरान दैनिक प्रेषण 1.74, 1.79 और 1.71 मिलियन टन रहा। अक्टूबर के पहले तीन दिनों में भी 1.75, 1.87 और 1.81 मिलियन टन प्रतिदिन आपूर्ति दर्ज की गई। घरेलू कोयले से बिजली उत्पादन भी पहली छमाही में बढ़कर 640.05 अरब यूनिट हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 582.5 अरब यूनिट था। कंपनी आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रथम मील संपर्क, तेज लदान प्रणाली और डिजिटल निगरानी पर भी जोर दे रही है।

स्पेशल खबर

मौद्रिक नीति समिति की बैठक, कल आरबीआई गवर्नर बताएंगे फैसला

रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो फरवरी 2023 के बाद यह पहली बार होगा जब रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी। इसके बाद रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो जाएगी। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 7 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा देंगे। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 में चार बार रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी। इससे



दर 6.50 प्रतिशत से घटकर 5.25 प्रतिशत रह गई थी। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक हुई चार मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्यौहारी मौसम में हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण

माना जा रहा है। अक्टूबर के दौरान वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आवास जैसे क्षेत्रों में कर्ज की मांग बढ़ती है। ऐसे में यदि रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों की बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दरों में तत्काल वृद्धि

हो सकती है। इससे नए कर्ज महंगे हो सकते हैं। वहीं, मौजूदा गृह ऋण और वाहन ऋण लेने वाले ग्राहकों की मासिक किस्त यानी ईएमआई भी बढ़ सकती है। इसका असर त्यौहारी मौसम में उपभोक्ता मांग पर पड़ने की संभावना है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बढ़ोतरी होने पर बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है। बैंक इस बढी हुई लागत का असर ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। इससे गृह ऋण, कार ऋण और व्यक्तिगत ऋण की ब्याज दरों तथा ईएमआई में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर, बैंक

जमा राशि आकर्षित करने के लिए सावधि जमा यानी एफडी की ब्याज दरें भी बढ़ा सकते हैं। रेपो रेट का इस्तेमाल रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है। महंगाई अधिक होने पर दर बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम करने की कोशिश की जाती है। इससे मांग घटने और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। इसके विपरीत, यदि अर्थव्यवस्था में सुस्ती होने पर धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए रेपो रेट में कटौती की जाती है, जिससे बैंकों के लिए कर्ज सस्ता होता है और ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अटकी बातचीत

समझौता टूटा नहीं, नए विकल्प मिलने पर आगे बढ़ सकती है बातचीत: सीतारमण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत फिलहाल ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है, जहां दोनों देशों के लिए आगे रियायत देना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में कहा कि भारत और अमेरिका अपनी-अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। हालांकि, बातचीत के लिए कोई नया रास्ता या अवसर बनता है तो दोनों देश उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

वित्त मंत्री के बयान का मतलब यह नहीं है कि व्यापार समझौते की बातचीत समाप्त हो गई है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने हितों से समझौता किए बिना आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहे हैं। व्यापार समझौते में दोनों देशों के लिए किसानों, कंपनियों और कारोबारियों के हित महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एक सीमा के बाद



अतिरिक्त रियायत देना कठिन हो जाता है।

अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्री ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार टैरिफ बढ़ाने की नीति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को आम तौर पर बातचीत और आपसी लेन-देन के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ चीन के व्यापार में भी बड़ा असंतुलन है, लेकिन केवल भारी शुल्क लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

सीतारमण ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का माहौल कठिन हो गया है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। ऐसे हालात में भारत के लिए व्यापार समझौतों का प्रमुख उद्देश्य देश के हितों की सुरक्षा करना है।

इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन इसे लागू होने में समय लग सकता है। दोनों पक्ष अटक हुए मुद्दों की पहचान कर उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 महीनों में बातचीत तीन बार टल चुकी है। अगस्त 2025 में अमेरिकी बैठक रह हुई, फरवरी 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा टला और हाल में अमेरिका ने तत्काल समझौते की संभावना से इनकार किया।

एवरेस्ट जीरा पाउडर का एक बैच असुरक्षित, एफएसएसएआई ने बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैकड जीरा पाउडर के एक बैच को असुरक्षित पाए जाने के बाद बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। जांच में उत्पाद में तय अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक कीटनाशक पाए गए। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एवरेस्ट जीरा पाउडर का नमूना गोवा स्थित मेसर्स रिक्साइड रिस्र्चेंस एंड हॉलीडे होम्स के परिसर से लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की जांच में एजॉक्सिस्ट्रोबिन और थियामेथोक्वसम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाए गए। कंपनी को रिपोर्ट को चुनौती देने का अवसर दिया गया, जिसके बाद नमूना रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। वहां की जांच में भी नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद एफएसएसएआई ने बैच नंबर ई080668761 वाले जीरा पाउडर को तत्काल बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए। कंपनी को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने और रिकॉर्ड की स्थिति की रिपोर्ट निर्धारित समय में जमा करने को कहा गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे मामले में क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के परिसर की जांच में खाद्य उत्पादन और रखरखाव वाले क्षेत्रों में गंदगी, धूल, ग्रीस, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। खराब होने वाली सामग्री खुले में रखी थी। जंग लगे और गंदे कंटेनरों का इस्तेमाल भी पाया गया। परिसर में कीट नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खाद्य उत्पादन क्षेत्र में कचरा, पुराना स्टील और कबाड़ जमा मिला। जंग लगे उपकरण, उखड़ा पेंट, सोलन और टूटी फर्श की टाइलों भी पाई गईं। पानी व तैयार खाद्य पदार्थों की जांच, तापमान निगरानी, उपकरण रखरखाव, प्रशिक्षण और शिकायतों से जुड़े जर्करी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे।

एसबीआई की ‘हर घर लखपति’ योजना में बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं निवेश

► 6.7 प्रतिशत सालाना ब्याज वाली आरडी योजना में 3 से 10 साल तक निवेश का विकल्प

हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो खाता माता-पिता या अभिभावक के साथ खोला जा सकता है। इस योजना में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद जमा राशि और ब्याज के आधार पर एकमुश्त रकम मिलती है। इसे नियमित बचत के माध्यम से तय वित्तीय लक्ष्य हासिल करने वाली योजना के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पांच साल में एक लाख रुपये का फंड तैयार करने का लक्ष्य रखा जाता है

तो हर महीने करीब 1,420 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, 10 साल में एक लाख रुपये जुटाने के लिए मासिक किस्त करीब 610 रुपये होगी।

योजना में बच्चों को सामान्य नागरिक की श्रेणी में रखा गया है। इस योजना में केवल एक लाख रुपये का लक्ष्य रखना जरूरी नहीं है। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार दो, तीन या चार लाख रुपये या उससे अधिक का लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उसके अनुसार मासिक किस्त की राशि भी तय होगी। योजना की अवधि और निर्धारित लक्ष्य के आधार पर नियमित रूप से किस्त जमा करनी होती है।

कूड़ा बीनने से स्वच्छता उद्यमी बनीं मेकाला

नईदुनिया ब्यूरो, गुटूर: आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली 30 वर्षीय मेकाला नंरारम्मा ने कूड़ा बीनने के काम से आगे बढ़कर स्थायी आजीविका की ओर कदम बढ़ाया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाली नंरारम्मा करीब 12 वर्षों से गुटूर नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा बीनने का काम कर रही थीं। सीमित और अनियमित आय के कारण उनके लिए परिवार का खर्च चलाना और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल था। नंरारम्मा को नवजीवन संगठन के माध्यम से स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सहायता अंतर्गत ट्रेक्टर पर लगे खुले नाले की सफाई करने वाले यंत्र की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। परियोजना की कुल लागत 16,99,952 रुपये थी। इसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सस्बिडी शामिल थी।